5 अप्रैल 2017

विश्व आर्थिक मंच पर विश्व नेता: अभिसरण या रुचियों का विसरण?

डॉ. अरुंधती शर्मा*

प्रति वर्ष स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित होनेवाला विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) का वार्षिक शिखर सम्मेलन विश्व नेताओं को अपने विचार तथा वैश्विक महत्त्व के मुद्दों पर अपने देश का दृष्टिकोण रखने का उपयुक्त मंच प्रदान करता है। हालांकि, पिछले दो शिखर सम्मेलनों का कुछ कारणों से अधिक महत्त्व रहा है। सर्वप्रथम, संरक्षणवाद तथा लोकप्रियतावाद के बढ़ते रुझानों के बीच शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जो ब्रेक्सिट मतदान तथा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की 'सर्वप्रथम अमेरिका की नीति' से प्रभावित थे।

दूसरा, पिछले दो वार्षिक शिखर सम्मेलनों में उभरती अर्थव्यवस्थाओं - भारत तथा चीन के नेताओं ने क्रमश: 2017 तथा 2018 में पहली बार मंच पर उद्घाटन भाषण दिया। इस लिहाज से वैश्विक समुदाय के लिए इन दो उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर ध्यान देना स्वाभाविक था। विशेषकर वैश्वीकरण तथा मुक्त व्यापार पर फिर से विश्वास कायम करने तथा एक साझा भविष्य तय करने में महत्त्वपूर्ण योगदान देने में उनकी भूमिका थी। जैसा, क्लाउस श्वाब ने कहा, *"इस रूपान्तर के बीच, भारत आशावाद तथा वादे की छवि प्रस्तुत करता है... इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत संक्रमण काल से गुजर रहा है तथा जल्द ही एक मजबूत ताकत बन जाएगा... वैश्विक नीति पर बहस को अधिक समृद्ध कर हमारे साझा भविष्य को आकार देने के लिए प्रभावित करने में, साथ*

ही एक समृद्ध विश्व का डिजाइन तैयार करने तथा विकास की दिशा में उसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेगी...”

इस परिप्रेक्ष्य में ये आलेख तीन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं - अमेरिका, चीन तथा भारत की स्थितियों का तुलनात्मक मूल्यांकन करने का प्रयत्न करेगा। इस प्रक्रिया में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तथा भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के व्याख्यानों की विवेचना करेगा।

व्याख्यानों का मूल्यांकन: दावोस में किसने क्या कहा?

तालिका 1 तीन नेताओं - अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तथा भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के व्याख्यानों का तुलनात्मक अध्ययन है। तीनों नेताओं के व्याख्यानों के मुख्य मुद्दे निम्नलिखित हैं:

- **वैश्वीकरण:** भारत तथा चीन दोनों वैश्वीकरण को सुरक्षित रखने के पैरोकार हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया की समस्या आर्थिक वैश्वीकरण का सीधा प्रभाव नहीं है, बल्कि वित्तीय पूंजी द्वारा अत्यधिक लाभ कमाने का प्रयास तथा वित्तीय नियमन की असफलता है। इसी प्रकार भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मानना था कि संरक्षणवाद के ताकतों से उत्पन्न समस्या का समाधान, जिसे कई समाजों तथा देशों ने स्वीकार किया है, वो ‘स्मार्ट तथा लचीली नीतियों’ के गठन में है, न कि पृथकतावाद में। विश्व की गतिविधियों में निरन्तर योगदान देने की मंशा स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी तथा राष्ट्रपति शी ने आर्थिक लचीलेपन के विस्तार तथा सम्बंधित देशों की वैश्विक आर्थिक पहुंच बढ़ाने पर बल दिया।

  हालांकि, अमेरिकी मुक्त व्यापार पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का रुख दिलचस्प था, जिन्होंने अपनी ‘अमेरिका सर्वप्रथम की नीति’ का उल्लेख करते हुए निष्पक्षता तथा पारस्परिकता के सिद्धांत पर बल दिया। कई अवसरों पर अपने कट्टर रुख के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस मंच पर मुक्त व्यापार का महत्त्व स्वीकार किया। हालांकि उन्होंने किसी विशिष्ट देश का नाम लिये बगैर बौद्धिक सम्पदा की चोरी, औद्योगिक सब्सिडी तथा देशों के नेतृत्व में व्यापक आर्थिक नियोजन समेत अनुचित आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख किया। फिर भी, अमेरिका के हितों की पैरोकारी करते हुए राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि “अमेरिका सर्वप्रथम का अर्थ अकेले सिर्फ अमेरिका नहीं है। जब

संयुक्त राज्य का विकास होगा तो दुनिया का भी विकास होगा।" इस अर्थ में राष्ट्रपति ट्रम्प विश्व समुदाय को पुन: आश्वस्त करते दिखे कि सर्वप्रथम अमेरिका नीति से पूरे विश्व का विकास होगा।

2. **वैश्विक प्रशासन**: तीनों नेताओं की बीच वैश्विक प्रशासन के मुद्दे पर विचारों का काफी अभिसरण दिखाई देता है। प्रधानमंत्री मोदी तथा राष्ट्रपति शी - दोनों नेताओं ने समकालीन समय की वास्तविकताओं को दर्शाने के लिए वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। दोनों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को अधिक समावेशी तथा प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में उभरते तथा विकासशील देशों के बढ़ते योगदान पर बल दिया। इस सिलसिले में, राष्ट्रपति शी ने विकासशील देशों की आवाज मजबूत करने तथा अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में 2010 कोटा सुधार को स्वीकार किया।

राष्ट्रपति ट्रम्प ने भी वैश्विक शासन, विशेषकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली में सुधार पर बात की। हालांकि, उन्होंने सुधार की प्रकृति पर विस्तारपूर्वक नहीं कहा। ये उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने चुनाव अभियान के समय से ही बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली तथा विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) पर संदेह जताया है। फिर भी, उन्होंने टीपीपी समेत परस्पर लाभकारी तथा सभी देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक समझौतों पर वार्ता के प्रति अपनी प्राथमिकता दिखाई है।

हालांकि, तीनों नेताओं के व्याख्यानों में एक महत्त्वपूर्ण अन्तर दिखाई देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने समग्र वैश्विक शासन वास्तुकला में विद्यमान असमानता के विषय में बात की, जिसमें 'प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक तथा सुरक्षा सम्बंधित संस्थान' शामिल हैं; राष्ट्रपति शी तथा राष्ट्रपति ट्रम्प ने सिर्फ वैश्विक आर्थिक तथा वित्तीय शासन के बारे में व्याख्यान दिया। उल्लेखनीय है कि अमेरिका तथा चीन दोनों ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की स्थाई सदस्यता का विस्तार करने में अनिच्छुक हैं।

3. **जलवायु परिवर्तन:** जलवायु परिवर्तन को प्रमुख खतरों में एक के रूप में मान्यता देते हुए, प्रधानमंत्री मोदी तथा राष्ट्रपति शी - दोनों ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के कार्य में अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रपति शी ने पेरिस समझौते को अपना समर्थन देते हुए कहा कि ये समझौता 'कठिन परिश्रम के बाद प्राप्त उपलब्धि' है तथा उन्होंने हस्ताक्षर करनेवाले सभी देशों से इसे पूरी तरह लागू करने की दिशा में कार्य करने

की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी उन नीतियों पर टिके रहे, जिसमें भारत ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएमए) समेत जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने की शुरुआत की है।

हालांकि, राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने व्याख्या में जलवायु परिवर्तन का उल्लेख नहीं किया। ये इस मुद्दे का अनुपालन न करने के उनके पुराने बयान का संकेत है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति ट्रम्प जून 2017 में पेरिस जलवायु समझौते से पीछे हट गए थे, जिसके लिए उन्होंने 'अमेरिका तथा उसके नागरिकों की सुरक्षा का हवाला दिया था।'

4. **आतंकवाद:** दावोस में अपने व्याख्यान में प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन के बाद आतंकवाद को मानव जाति के लिए दूसरा सबसे बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि 'बुरे' और 'अच्छे' आतंकवाद के रूप में भेद करना एक खतरनाक प्रवृत्ति है। इसके अलावा शिक्षित युवकों को कट्टपंथियों द्वारा आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करना भी गंभीर चिन्ता का विषय है। इसलिए, उन्होंने मंच से आतंकवाद तथा आतंकवाद सम्बंधित गतिविधियों के कारण उत्पन्न 'दरार' पर चर्चा करने तथा इसका समाधान ढूढ़ने का आग्रह किया। इसी तर्ज पर राष्ट्रपति ट्रम्प ने इराक, सीरिया तथा अफगानिस्तान जैसे प्रभावित देशों से आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने की बात कहते हुए इसकी निन्दा की। उन्होंने कहा कि उनका देश आईएसआईएस जैसे जिहादी संगठनों को उखाड़ फेंकने तथा क्षेत्रों और जनसंख्या पर से आतंकवादी संगठनों का प्रभाव समाप्त करने के लिए मित्र देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है, ताकि उनका वित्त पोषण तथा उनकी विचारधारा समाप्त की जा सके।

हालांकि चीन के राष्ट्रपति ने आतंकवाद को हल्के-फुलके ढंग से लिया, जो उनके अनुसार वैश्विक अनिश्चितता के कारण उत्पन्न कई वैश्विक चुनौतियों में से एक है।

5. **प्रौद्योगिकी:** अपने मुख्य विन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री मोदी तथा राष्ट्रपति - दोनों ने वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी की प्रासंगिकता का उल्लेख किया। दोनों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रौद्योगिकी के महत्त्व तथा उसके नकारात्वक प्रभाव की बात की। इसके अलावा दोनों ने समाज के अधिक लाभ के लिए इसकी आवश्यकता पर बल दिया। फिर भी, प्रधानमंत्री मोदी ने जहां गरीबी तथा बेरोजगारी दूर करने में प्रौद्योगिकी के योगदान की संभावनाओं पर बल दिया, वहीं राष्ट्रपति शी ने कहा कि 'विकास के नए स्रोतों का सामने आना अभी बाकी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए नया रास्ता अभी छिपा हुआ है।' लेकिन राष्ट्रपति ट्रम्प के व्याख्या में प्रौद्योगिकी पर कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं था।

6. **राष्ट्रीय हित:** मंच ने तीनों नेताओं को अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने तथा उनके प्रशासन द्वारा उनकी अर्थव्यवस्थाओं में सुधार के प्रयासों के बारे में बताने का अवसर प्रदान किया। तीनों देशों के नेताओं ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं में विदेशी निवेश की अपार संभावनाओं का उल्लेख करते हुए अपने राष्ट्रीय हित स्पष्ट किये। हालांकि जहां राष्ट्रपति शी पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास में चीन के योगदान पर बल देते रहे, प्रधानमंत्री मोदी तथा राष्ट्रपति ट्रम्प का जोर अपने-अपने देशों में भविष्य में निवेश की संभावनाओं के बारे में बताने पर था।

7. **वैश्विक दृष्टिकोण:** जहां तक साझा चुनौतियों का सामना करने तथा बेहतर भविष्य का सवाल है, तो सहयोग तथा उसके संदर्भ में विचारों का अभिसरण प्रतीत होता है। इस दिशा में चीन ने, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए भारत के साथ सहयोग बढ़ाने में पहले ही दिलचस्पी व्यक्त की है। वैश्वीकरण पर प्रधानमंत्री मोदी के रुख की सराहना करते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने टिप्पणी की,

"चीन तथा भारत कई आम हितों को साझा करते हैं। चीन वैश्विक आर्थिक विकास के लिए भारत समेत सभी देशों के साथ समन्वय तथा सहयोग बढ़ाना चाहता है, ताकि विश्व की अर्थव्यवस्था का विकास हो तथा सभी देशों का कल्याण हो"।

सारणी1 : विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएच) पर वैश्विक नेताओं के भाषणों का मूल्यांकन

मुद्दे/ देश	**@अमेरिका**	**^चीन**	**#भारत**
वैश्वीकरण	"... अगर कोई देश दूसरे देशों का शोषण कर व्यवस्था का लाभ उठाता है, तो हम स्वतंत्र तथा मुक्त व्यापार नहीं कर सकते।" बैद्धिक सम्पदा की चोरी, औद्योगिक सब्सिडी तथा देशों	"...कई वैश्विक समस्याएं आर्थिक वैश्वीकरण का परिणाम नहीं हैं ....ये आर्थिक वैश्वीकरण का अपरिहार्य नतीजा नहीं है; बल्कि वित्तीय पूंजी से अधिक लाभ उठाने की कोशिश तथा वित्तीय	कई समाजों में वैश्वीकरण सिकुड़ रहा है तथा देश अधिक से अधिक आत्म-केन्द्रित हो रहे हैं। नए प्रकार के कर तथा करमुक्त सीमाओं में संरक्षणवाद की ताकतें स्पष्ट हैं, द्वीपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार समझौतों में गतिरोध तथा अधिकांश देशों में

	के नेतृत्व में अनुचित आर्थक योजनाओं जैसे अनुचित क्रियाकलापों के बिना मुक्त व्यापार का समर्थन करें। “सिर्फ मुक्त तथा दोतरफा व्यापार पर बल देकर हम एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं, जो न सिर्फ अमेरिका, बल्कि सभी देशों के लिए लाभदायक हो।”	संस्थाओं की गंभीर असफलता के कारण है। वैश्विक समस्याओं के लिए सिर्फ आर्थिक वैश्वीकरण पर आरोप मढ़ना सच्चाई से दूर भागना है, और इससे समस्याओं का समाधान नहीं होगा।” “ये सत्य है कि आर्थिक वैश्वीकरण ने नई समस्याएं उत्पन्न की हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आर्थिक वैश्वीकरण को पूरी तरह उन्मूलन कर दिया जाए। बल्कि, हमें आर्थिक वैश्वीकरण को दिशा-निर्देश देना चाहिए, इसके नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करना चाहिए तथा इसका लाभ सभी देशों को उपलब्ध कराना चाहिए।” “... वैश्विक अर्थव्यस्था एक विशाल समुद्र है,	सीमा-पार वित्तीय निवेश में कमी और वैश्विक सप्लाई श्रृंखला में कमी आई है। इस संरक्षणवाद का समाधान ‘अलगाववाद के बजाय स्मार्ट तथा लचीली नीतियां बनाने में है।’

		जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के बीच वित्त, प्रौद्योगिकी, उत्पाद, उद्योग तथा लोगों में किसी भी प्रकार की कटौती करना समुद्र के पानी को वापस झीलों और तालाबों की ओर मोड़ने जैसा है, जो संभव नहीं है।" "... हमें वैश्विक मुक्त व्यापार के विकास के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, व्यापार तथा निवेश, उदारीकरण, नई संभावनाएं तलाशकर तथा संरक्षणवाद पर लगाम को प्रोत्साहन देना चाहिए। संरक्षणवाद का अर्थ एक अंधेरे कमरे में खुद को देखने के समान है... व्यापार के युद्ध में किसी की जीत नहीं होगा।" "चीन न सिर्फ	

		आर्थिक वैश्वीकरण से लाभान्वित हुआ है, बल्कि इसने इसके लिए योगदान भी दिया है"। "चीन की नीयत आरएमबी का अवमूल्यन कर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देने की नहीं है, फिर भी मुद्रा युद्ध आरम्भ होगा।"	
वैश्विक प्रशासन	"... हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली को सुधारने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं, ताकि विस्तृत रूप से सम्पन्नता को प्रोत्साहन मिले तथा नियमों के अनुसार चलनेवाले पुरस्कृत हों।" "...संयुक्त राज्य सभी देशों के साथ आपसी लाभ, द्विपक्षीय व्यापारिक समझौतों के लिए तैयार है। ये टीपीपी में स्थित देशों के लिए भी मान्य है, जो आवश्यक हैं।"	अपर्याप्त वैश्विक आर्थिक प्रशासन, वैश्विक अर्थव्यवस्था में नए विकास के रास्ते में रुकावट हैं। नए बाजार तथा विकासशील देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में पहले ही 80 प्रतिशत का योगदान दे रहे हैं। वैश्विक परिदृश्य ने उन परिवर्तनों को स्वीकार नहीं किया है, लिहाजा प्रतिनिधित्व तथा संलग्नता के मामले में अपर्याप्त है। "...हमें समय के	संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व व्यापार संगठन जैसी पुरानी व्यवस्था तथा विकासशील देशों की आवश्यकताओं के बीच असमानता स्पष्ट होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय नियमों पर आधारित प्रणाली पर टिके रहना चाहिए तथा अंतरराष्ट्रीय नियम-कानूनों के स्वरूप पर सही अर्थों में टिकना चाहिए। प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक तथा सुरक्षा से जुड़ी संस्थाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देकर तथा लोकतांत्रिक बनाकर बदलती दुनिया की वास्तविकताओं के अनुरूप सुधार करना चाहिए।

		अनुरूप स्वच्छ तथा समानता के आधार पर प्रशासन का नमूना विकसित करना चाहिए.... वैश्विक आर्थिक प्रशासन में सुधार लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय में मांग बढ़ रही है... अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शिल्प में नई गतिशीलता आने पर ही वैश्विक प्रशासन प्रणाली में वैश्विक विकास होगा।" "बड़े हों या छोटे, मजबूत हों या कमजोर, धनी हों या गरीब - सभी देश अंतरराष्ट्रीय समुदाय में बराबरी के सदस्य हैं। इस लिहाज से वो फैसला लेने में, अधिकारों का उपयोग करने में तथा जिम्मेदारी निभाने में बराबरी के हिस्सेदार हैं। उभरते हुए बाजार तथा विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व और उनकी आवाज	

		अधिक मजबूत होनी चाहिए।" "2010 का अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कोटा सुधार लागू हो गया है, तथा इसकी रफ्तार बनाए रखनी चाहिए। हमें बहुपक्षीय संस्थानों के अधिकार तथा प्रभाव बनाए रखने के लिए बहुपक्षवाद का पालन करना चाहिए। हमें वादे पूरे करने चाहिए, तथा नियमों का पालन करना चाहिए।"	
जलवायु परिवर्तन	एन.आर.	"भारी कठिनाईयों का सामना करने के बाद पेरिस समझौता सम्पन्न हुआ है, जो वैश्विक विकास के दौर को ध्यान में रखते हुए है। इस समझौते पर सभी हस्ताक्षर करनेवालों को इससे भागने के बजाय इसपर टिके रहना चाहिए, क्योंकि ये आनेवाली पीढ़ियों के लिए	जलवायु परिवर्तन को सबसे बड़ा खतरा करार दिया। "ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं, आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है और कई द्वीप या तो डूब गए हैं या डूबने के कगार पर हैं। चरम ठंड तथा गर्मी, आवश्यकता से अधिक बारिश और बाढ़ या अकाल - जलवायु परिवर्तन का कुअसर दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। इन परिस्थितियों में, हमें अपने संकीर्ण हितों को छोड़कर एकजुट हो जाना

		हमारी जिम्मेदारी है।"	चाहिए।" "पर्यावरण की सुरक्षा तथा जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए मेरी सरकार ने देश के सामने काफी विशाल लक्ष्य रखा है। भारत में 2022 तक हमें 175 गीगावॉट नवीकृत ऊर्जा का उत्पादन करना है तथा पिछले तीन वर्षों में हमने 60 गीगावॉट का उत्पादन आरम्भ कर दिया है, जो लक्ष्य के एक-तिहाई से अधिक है।" अंतरराष्ट्रीय सौर संधि (आईएसए) को देशभर में ऊर्जा संसाधन का स्रोत तलाशने की जिम्मेदारी दी गई है।
आतंकवाद	"...अपने देश की सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे, हम उठाएंगे। हम अपने नागरिकों तथा अपनी सीमाओं की रक्षा करेंगे। राष्ट्रीय तथा आर्थिक हितों को देखते हुए हम अपनी प्रवास प्रणाली को भी	"...आतंकवाद तथा शरणार्थी समस्या और गरीबी, बेरोजगारी तथा आमदनी में बढ़ते अन्तर जैसी अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों ने वैश्विक अनिश्चितता को बढ़ाया है।"	आतंकवाद को दूसरा प्रमुख खतरा बताया। 'बुरे' तथा 'अच्छे' आतंकवाद के अन्तर को खतरनाक चलन करार दिया। शिक्षित युवकों को आतंकवादी बनाना। मंच से आतंकवाद तथा आतंकवाद से उत्पन्न दरार से जुड़ी समस्याओं पर विचार-विमर्श के लिए

	मजबूत बना रहे हैं।" "हम मित्रों तथा सहयोगियों के साथ आईएसआईएस जैसे जिहादी संगठनों के खात्मे का प्रयास कर रहे हैं तथा आतंकवादियों का क्षेत्रों तथा जनसंख्या पर नियंत्रण समाप्त करने, उनका वित्त पोषण समाप्त करने तथा उनकी दुष्ट विचारधारा को खत्म करने के लिए बेहद विस्तृत सहयोग कर रहे हैं।" "...गठबंधन ने आईएसआईएस को हराकर इराक तथा सीरिया में लगभग 100 प्रतिशत क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है, जिसपर कभी आतंकवादियों का कब्जा था।" "हम ये सुनिश्चित करने पर प्रतिबद्ध हैं कि अफगानिस्तान फिर कभी आतंकवादियों		आह्वान किया।

	का सुरक्षित पनाहगार न बनने पाए, जो नरसंहार में विश्वास रखते हैं।"		
प्रौद्योगिकी	**N.R.**	"कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा 3-डी प्रिंटिंग जैसी नई प्रौद्योगिकियों के उद्भव के बावजूद विकास के नए स्रोतों का आविष्कार अभी बाकी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए नया रास्ता अभी स्पष्ट नहीं है।" "हमें प्रायोगिक आईटी तथा रोजगार में स्वचालन के नकारात्मक प्रभावों पर ध्यान देना चाहिए। नए उद्योग तथा व्यापार की नई पद्धितियां प्रारम्भ करते हुए हमें नए रोजगार उत्पन्न करने चाहिए तथा लोगों में विश्वास तथा आशा जगाए रखना चाहिए।"	दुनिया की आर्थिक प्रगति त्वरित करना आवश्यक है। इस दिशा में प्रौद्योगिकी तथा डिजिटल परिवर्तन गरीबी तथा बेरोजगारी जैसी समस्याओं से निपटने में मदद कर सकती हैं।
राष्ट्रीय हित	"अमेरिका के राष्ट्रपति होने के	"चीन का शानदार विकास, उपलब्धियां	"समावेशी आर्थिक विकास के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों के

	नाते मैं हमेशा अमेरिका पहले की नीति की पैरोकारी करूंगा, जिस प्रकार अन्य देशों के नेता भी अपने देशों के हितों को सर्वप्रथम रखते हैं।" "अमेरिका व्यापार करने का स्थान है। लिहाजा, अगर आप आविष्कार, उत्पादन तथा निर्माण करना चाहते हैं, तो अमेरिका आएं।" "दुनिया एक मजबूत तथा सम्पन्न अमेरिका की उत्पत्ति का गवाह बन रही है... अमेरिका में किराए पर लेने, निर्माण करने, निवेश करने तथा विकास करने का इससे बेहतर मौका नहीं आएगा और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम प्रतिस्पर्धात्मक हैं।" "अमेरिका सर्वप्रथम का तात्पर्य ये नहीं कि अमेरिका	तथा लोगों की जीवन शैली में तेज सुधार चीन तथा दुनिया - दोनों का ही आशीर्वाद है।" "हम दूसरों से चीन का विकास करने की आशा नहीं रख सकते, तथा ऐसा करने की स्थिति में कोई नहीं है। "जब चीन के विकास का मूल्यांकन किया जाता है, तो सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि चीन की जनता को क्या लाभ हुआ... बल्कि ये भी देखना चाहिए कि चीन ने वैश्विक विकास में क्या योगदान दिया है।" "चीन का विकास दुनिया के लिए एक अवसर है...चीन का तेज विकास वैश्विक आर्थिक स्थायित्व तथा विस्तार के लिए एक दीर्घकालीन ताकतवर इंजन है।"	समन्वय में सभी प्रकार के अन्तर को पाटने की क्षमता है।" "हमने सुधार, प्रदर्शन तथा परिवर्तन का मार्ग चुना है। आज जिस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश किया जा रहा है, वो अतुल्य है....अर्थव्यवस्था के लगभग सभी अंग विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए खुले हुए हैं। 90 प्रतिशत से अधिक मामलों में चैनलों के द्वारा निवेश करना संभव है।" "मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि अगर आप अच्छाई के साथ सपन्नता चाहते हैं तो भारत में कार्य करें। अगर आप स्वास्थ्य के साथ जीवन की सम्पूर्णता चाहते हैं तो भारत आएं। अगर आप सम्पन्नता के साथ शांति चाहते हैं तो भारत में रहें। अगर आप भारत आते हैं यहां आपका हर समय स्वागत है।"

	अकेले। जब अमेरिका का विकास होगा तो दुनिया का भी विकास होगा।”	“चीन की अर्थव्यवस्था का जिस दौर में प्रवेश हुआ है, उसे हम नया सामान्य दौर कहते हैं, जिसमें विकास दर, विकास मॉडल, आर्थिक संरचना तथा विकास के कारकों के संदर्भ में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं।” “2016 में चीन की अर्थव्यवस्था में 6.7 प्रतिशत की दर से विकास की आशा है, जो दुनिया में सबसे तेज रफ्तार विकास में एक है।” बेल्ट एंड रोड की शुरुआत चीन में हुई, लेकिन इसका लाभ सीमा से बाहर भी हो रहा है। चीन आपूर्ति में सुधार, अत्यधिक क्षमता कम करने, सूची में कमी लाने, वित्त पोषण कम करने, लागत कम करने तथा कमजोर	

		कड़ी को मजबूत कर आर्थिक विकास बढ़ाने का प्रयास करेगा। ये नवीनता पर आधारित रणनीतिक विकास के साथ नया उत्साह जोड़कर बाजार को दीर्घकालीन तथा मजबूत बनाएगा। चीन विदेशी निवेशकों के लिए बाजार की पहुंच बढ़ाने, उच्च मानकों वाले पायलट मुक्त व्यापार क्षेत्रों का निर्माण करने, सम्पत्ति के अधिकारों की सुरक्षा मजबूत करने तथा चीन के बाजार को अधिक पारदर्शी और अधिक विनियमित कर क्षेत्र का स्तर बढ़ाकर निवेश के लिए एक सक्षम तथा व्यवस्थित वातावरण को प्रोत्साहन देगा। चीन एशिया-प्रशांत क्षेत्र में मुक्त व्यापार क्षेत्र के	

		निर्माण तथा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) की वार्ता को मुक्त व्यापार समझौतों के वैश्विक नेटवर्क के निर्माण के लिए सामान्य विकास के लिए खोलने में बाहरी वातावरण को मजबूती से प्रोत्साहन देगा।	
वैश्विक दृष्टिकोण	एक बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अमेरिका अपनी दोस्ती तथा भागीदारी की पुष्टि करता है।	"जब तक हम मानव जाति के लिए साझा भविष्य के लक्ष्य निर्माण को बनाए रखते हैं तथा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने और कठिनाईयों को दूर करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं, तब तक हम एक बेहतर दुनिया के निर्माण में तथा अपने लोगों को एक बेहतर जीवन शैली प्रदान करने में सक्षम होंगे।"	साझा चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रमुख देशों के बीच प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग के साथ मतभेदों को दूर करना होगा तथा दूरदृष्टि के लिए कार्य करना होगा।

स्रोत @ - व्हाइट हाउस, "रिमार्क्स बाई प्रेसिडेंट ट्रम्प टूद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम",

जनवरी 26, 2018, https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-world-economic-forum/ ; ^ - डब्ल्यूईएफ, "प्रेसिडेंट शीज़ स्पीच टू दावोस इन फुल", जनवरी 17, 2017, https://www.weforum.org/agenda/2017/01/full-text-of-xi-jinping-keynote-at-the-world-economic-forum ; # - एमईए, "प्राइम मिनिस्टर्स स्टेटमेंट ऑन द सब्जेक्ट "क्रियेटिंग ए शेयर्ड फ्यूचर इन अ फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड" इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (जनवरी 23, 2018)", http://mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/29378/Prime_Ministers_Keynote_Speech_at_Plenary_Session_of_World_Economic_Forum_Davos_January_23_2018

एन. आर. - कोई उल्लेख नहीं

उपसंहार

डब्ल्यूईएफ में अमेरिका, चीन तथा भारत तीनों देशों के नेताओं के तुलनात्मक मूल्यांकन से पता चलता है कि उन्होंने मजबूती से अपने-अपने देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में बताया, मंच पर उपस्थित लोगों का ध्यान वैसी वैश्विक चुनौतियों की ओर आकर्षित किया, जो वर्तमान समय में मुंह बाए खड़ी हैं तथा उनसे निपटने के लिए सहयोग का आह्वान किया।

भाषण के विश्लेषण से संकेत मिलते हैं कि वैश्वीकरण के मुद्दे पर अमेरिका की तुलना में भारत तथा चीन के विचार में अधिक अभिसरण है। प्रधानमंत्री मोदी तथा राष्ट्रपति शी - दोनों ने वैश्विक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान के लिए वैश्वीकरण की ताकतों को मजबूत बनाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। राष्ट्रपति शी ने सही टिप्पणी की, "चीन न सिर्फ आर्थिक वैश्वीकरण से लाभान्वित हुआ है, बल्कि इसमें योगदान भी दे रहा है।" राष्ट्रपति ने मुक्त व्यापार की पैरोकारी करते हुए वैश्वीकरण की वकालत अवश्य की, साथ ही बौद्धिक सम्पदा अधिकार, औद्योगिक सब्सिडी तथा देशों के नेतृत्व में होने वाली अनुचित आर्थिक योजनाओं जैसे क्रियाकलापों को लेकर चेतावनी भी दी।

भारत तथा चीन के बीच जलवायु परिवर्तन, वैश्विक प्रशासन तथा प्रौद्योगिकी को लेकर स्पष्ट अभिसरण तथा भिन्नताएं हैं। उदाहरणार्थ, वैश्विक प्रशासन के मुद्दे पर राष्ट्रपति शी ने आर्थिक तथा वित्तीय संस्थाओं में सुधार के बारे में कहा, लेकिन सुरक्षा से जुड़ी संस्थाओं को लेकर चुप्पी साध गए। हालांकि वैश्विक प्रशासन के मसले पर प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्य में राजनीतिक, आर्थिक तथा सुरक्षा से जुड़ी संस्थाएं भी शामिल थीं।

आतंकवाद के मुद्दे पर भारत तथा अमेरिका के बीच हितों का अधिक अभिसरण दिखाई दिया। इस सम्बंध में प्रधानमंत्री मोदी तथा राष्ट्रपति ट्रम्प ने मंच पर मजबूती से आतंकवाद के विरुद्ध बयान

दिये। जबकि चीन के राष्ट्रपति ने आतंकवाद पर विस्तार से कुछ नहीं कहा, सिवाय कुछ औपचारिक वक्तव्यों के।

सहयोग के आधार पर विशेषकर भारत तथा चीन के बीच साझा वैश्विक हितों पर दृष्टिकोण का अभिसरण अधिक मजबूत दिखता है। लेकिन अभी ये देखना बाकी है कि ये अभिसरण वास्तविकता के धरातल पर किस प्रकार आपसी सहयोग बढ़ाकर भविष्य में वैश्वीकरण को मजबूती देते हैं।

***

* *डॉ. अरुंधती शर्मा, शोध अध्येता, विश्व मामलों की भारतीय परिषद, (आईसीडब्ल्यूए), सप्रु हाउस, नई दिल्ली।*

डिस्क्लेमरः उपरोक्त विचार शोध अध्येता के निजी विचार हैं तथा परिषद के विचारों को प्रतिबिम्बित नहीं करते।